

25.09.2025 / प्रादेशिक समाचार / 19:45 बजे

मुख्य समाचार

- प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए एंटी-चिट्टा वॉलंटियर योजना शुरू करेगी राज्य सरकार— 17 स्वयंसेवी संस्थाएं नशे के खिलाफ चलाएंगी जागरूकता अभियान।
- राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत अभी तक प्रदेश में 6 लाख से अधिक ओपीडी सेवाओं का आयोजन।
- प्रदेश के हर जिले में हिमुडा बनाएगा कॉलोनी—लोगों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं।
- भारत नेट योजना के तहत प्रदेश की 3 हजार 6 सौ 15 ग्राम पंचायतों को मिलेगी हाईस्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।

एंटी-चिट्टा

राज्य सरकार नशे की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से एंटी-चिट्टा वॉलंटियर योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत एक हजार से अधिक एंटी चिट्टा वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे जो पुलिस व लोगों सहित अन्य हितधारकों के बीच एक मजबूत सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर शुरू की जा रही इस नई योजना से जमीनी स्तर पर खुफिया तंत्र सुदृढ़ करने, युवाओं व समाज में जागरूकता लाने, प्रभावितों को पुर्नवास सेवा प्रदान की जाएगी। योजना के तहत पंजीकृत स्वयंसेवियों को सेवाओं के लिए मानदेय भी प्रदान किया जाएगा।

चिट्टामुक्त पहल

प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे चिट्टे के प्रयोग के खिलाफ शिमला में विभिन्न संस्थाओं ने मिलकर हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाने की पहल शुरू की है। सात जिलों की 17 स्वयंसेवी संस्थाएं 'संजिवनी' संस्था के बैनर तले एक मंच पर आई और सर्वसम्मति से नशे के खिलाफ एक व्यापक जन अभियान शुरू करने का संकल्प लिया है। संस्था के अध्यक्ष महेंद्र धर्माणी ने आज शिमला में बताया कि नशा हिमाचल के युवाओं को खोखला कर रहा है और अब समय आ गया है कि समाज, सरकार और प्रशासन मिलकर निर्णायक लड़ाई लड़ें। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में 'चिट्टा' नामक सिंथेटिक ड्रग ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। उन्होंने कहा कि गृह विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पकड़े जाने वाले नशे की

मात्रा असली खपत का केवल 2 से 3 प्रतिशत होती है। महेन्द्र धर्माणी ने बताया कि 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इस दौरान कम से कम 5 हजार लोगों से सीधा संपर्क कर उन्हें नशा मुक्ति से जोड़ा जाएगा। धर्माणी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे की दलदल से बाहर निकालना है।

अभियान

राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक महिलाओं को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अभियान के तहत प्रदेश में अभी तक 6 लाख 57 हजार से अधिक ओपीडी सेवाएं प्रदान की गयी जिनके माध्यम से उच्च रक्तचाप, कैंसर और टीबी सहित अन्य बीमारियों की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि अभियान के तहत एक हजार 6 सौ 93 आयुष्मान कार्ड धारकों को वित्तीय व स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान महिलाओं की जांच में जो रोग पाए गए हैं। उन सभी को आवश्यक निदान व उपचार और फॉलोअप सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने महिलाओं से अभियान के तहत अपनी जांच करवाने का आग्रह किया है।

शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण व रोजगार सृजन पर बल दिया है। सोलन जिला के सायरी में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आयोजित बहुविशेषज्ञ स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारम्भ करने के बाद लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि लोगों को बेहतर उपचार प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने प्रदेश को नशामुक्त राज्य बनाने के लिए सभी से सहयोग का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनीं।

स्वास्थ्य जांच

इस बीच पत्र सूचना कार्यालय शिमला द्वारा दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल रिपन की टीम के सहयोग से सी.जी.ओ. परिसर के सभी कार्यालयों के स्टॉफ की जांच के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान बी.पी., शुगर और हीमोग्लोबिन सहित विभिन्न प्रकार की जांच की गई। शिविर का उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा संचालित स्वच्छता अभियान के तहत सफाई मित्रों के स्वास्थ्य की जांच करना था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस महीने की 17 तारीख को शुरू किए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत ऐसे शिविर अनेक स्थानों पर लगाए जा रहे हैं।

हर्षवर्धन चौहान

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सरकारी व निजी संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना होगा। आज सोलन में एक निजी विश्वविद्यालय द्वारा विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्र में फार्मासिस्ट लोगों को घर-द्वार पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि बद्दी-बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र में करीब 6 सौ से अधिक फार्मा कंपनियां कार्यरत हैं।

हिमुडा

हिमाचल प्रदेश आवास व शहरी विकास प्राधिकरण हिमुडा प्रदेश के हर जिले में एक-एक कालोनी बनाएगा जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। हिमुडा के सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेन्द्र वशिष्ठ ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि हिमुडा किफायती दरों पर लोगों को मकान उपलब्ध करवाता है।

सेवा पर्व

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर, परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज, इस विशेष श्रृंखला – 'सेवा पर्व' में, हम बात कर रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने रक्षा उत्पादन को मजबूत किया है, जिससे भारत आत्मनिर्भर बना है और वैश्विक रक्षा बाज़ार में वह एक उभरती हुई शक्ति बन गया है। एक रिपोर्ट.....

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता नरेन्द्र मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेड इन इंडिया की ताकत देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर दिया है...

आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी कि दुश्मन को पता तक ना चला कौन सा शस्त्र है कि कौन सा सामर्थ्य है पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए अगर हम आत्मनिर्भर ना होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी बड़ी गति से हम कर पाते। पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही।

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में, वार्षिक रक्षा उत्पादन 2024-25 में एक लाख 50 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया, जो 2014-15 के

मुकाबले तीन गुना से भी ज़्यादा है। उद्योग के सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने पिछले एक दशक में दूरगामी नीतिगत सुधारों, व्यापार में बढ़ती सुगमता और स्वदेशीकरण पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने से साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की है। मेक-इन-इंडिया भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनिवार्य घटक है। इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रभावी कार्रवाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रणनीतिक नीतियों और स्वदेशी नवाचारों से प्रेरित रक्षा उत्पादन में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता ने राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया है। बढ़ते निर्यात और मेक इन इंडिया जैसी पहल अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में देश की एक प्रमुख क्षमता बनने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

दूरसंचार

केन्द्रीय संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा हिमाचल में नागरिक केन्द्रित पहलों से मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। आज शिमला में एक पत्रकारवार्ता के दौरान दूरसंचार विभाग के अप्पर महानिदेशक अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि केन्द्र की फोर-जी संतृप्ति और भारत नेट योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी नेटवर्क को मजबूत किया गया है। उन्होंने बताया कि फोर-जी संतृप्ति योजना के तहत अब तक 4 सौ 98 साइट लगाई गई हैं जबकि भारत नेट योजना के अंतर्गत 3 हजार 6 सौ 15 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना है।

उन्होंने बताया कि डिजिटल इंटेलीजेंस प्लेटफॉर्म, संचार साथी, संचार मित्र योजना और वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक एफआईआर के माध्यम से लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए एंटी-चिट्टा वॉलंटियर योजना शुरू करेगी राज्य सरकार— 17 स्वयंसेवी संस्थाएं नशे के खिलाफ चलाएंगी जागरूकता अभियान।
- राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत अभी तक प्रदेश में 6 लाख से अधिक ओपीडी सेवाओं का आयोजन।
- प्रदेश के हर जिले में हिमुडा बनाएगा कॉलोनी—लोगों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं।
- भारत नेट योजना के तहत प्रदेश की 3 हजार 6 सौ 15 ग्राम पंचायतों को मिलेगी हाईस्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।